रेड कार्ड इन नेपाल

साभार: इंडियन एक्सप्रेस *(06 अक्टूबर, 2017)*

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

कम्युनिस्ट दलों के प्रस्तावित एकीकरण में खुलापन और विश्वसनीयता का अभाव है। इसलिए यहाँ परेशान राजनीतिक के शांत होने की संभावना बहुत कम है।

आगामी प्रांतीय और संघीय संसद चुनाव से पहले एक गठबंधन बनाने के लिए नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी-यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-माओवादी केंद्र के नेताओं की आश्चर्यजनक घोषणा ने देश में एक और दौर की राजनीतिक अनिश्चितता की शुरुआत कर दिया है। एक एकीकृत साम्यवादी पार्टी बनाने की ओर गठबंधन सबसे पहले कदम माना जाता है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली सरकार के लिए एकीकरण प्रक्रिया का अशुभ प्रभाव पड़ा है, चूंकि पुष्पा कमल दहल की अगुआई में सीपीएन-माओवादी केंद्र सरकार का एक हिस्सा है, जबकि उसका नया पार्टनर, सीपीएन-माओवादी सेंटर ऑफ के.पी. ओली, मुख्य विपक्षी समूह है। हालांकि, दहल ने दावा किया है कि कम्युनिस्ट गठबंधन ने शेर बहादुर देउबा की सरकार के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया है, नेपाली कांग्रेस ने विकास को विश्वासघात कहा है। नई दिल्ली के लिए चिंता का कारण चीनी कम्युनिस्टों द्वारा एक दूसरे के प्रति विभिन्न कम्युनिस्ट गुटों को प्रेरित करना है, अर्थात ओली के सीपीएन-यूएमएल में गठबंधन की प्रमुख पार्टी को बीजिंग के नजदीक माना जाता है।

गठबंधन के आसपास की गोपनीयता नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है। दलों के प्रसार, उनके लगातार विभाजन और केवल कार्यालय की खातिर गठबंधनों को बनाने और तोड़ने के लिए राजनीतिक वर्ग की इच्छा ने सरकार में अस्थिरता उत्पन्न की और लोकतांत्रिक परिवर्तन की विश्वसनीयता को कम कर दिया। एक सद्भावना सलाहकार प्रक्रिया के माध्यम से एक को तैयार करने के बजाय, एक संविधान लागू करने के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठान की कोशिश ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। संविधान पर सर्वसम्मति की कमी ने काठमांडू को मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण से स्पष्ट रूप से परिभाषित जनादेशों के निर्माण से हाथ मिलाया है, जिससे प्रभावशाली पार्टियों को निजी एजेंडा को आगे बढ़ाने और मांग को प्रोत्साहित करने की इजाजत मिलती है। साम्यवादी पुनर्मिलन प्रक्रिया भी षड्यंत्रकारी दृष्टिकोण का पालन कर रही है जिसने पूर्व में सरकार गठन को परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए, सीपीएन 1990 के दशक में वैचारिक मतभेदों पर विभाजित था और दहल के तहत माओवादी गुट ने एक सशस्त्र संघर्ष करने की चाह रखी। माओवादियों ने रेखा को संशोधित किया और 2005 में शांति प्रक्रिया में शामिल हो गए, जिससे नेपाल के एक राजशाही से एक लोकतांत्रिक गणराज्य के संक्रमण को सक्षम बनाया गया। माओवादियों का एक बार से अधिक बार विभाजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ नेता बाबूराम भट्टराई ने यह घोषणा करते हुए कहा कि अब साम्यवाद अप्रासंगिक हो गया है, भट्टराई मंगलवार को हुए गठजोड़ घोषणापत्र के हस्ताक्षरकर्ता हैं।

एकीकरण की प्रक्रिया, जिसमें यह वैचारिक आधारभूत प्रतीत होता है कि नेताओं के समूह की धारणा एक साथ तभी मिलती है, जब चुनाव के वक्त शक्ति जुटाने की होड़ मची होती हैं। इसलिए यहाँ लोगों के बीच विश्वास पैदा करने की संभावना बिकुल भी नहीं है।

इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

भारत-नेपाल मैत्री संधि

अनेक कूटनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप 1950 में भारत और नेपाल के मध्य मैत्री संधि हुई।

संधि के प्रावधान

- दोनों देशों ने एक-दूसरे की सुरक्षा की गारंटी ली।
- एक-दूसरे के विरूद्ध विदेशी आक्रमण को सहन नहीं करेंगे।
- नेपाल अपनी युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा।
- यदि नेपाल युद्ध सामग्री किसी अन्य देश से खरीदता है तो वह भारत से होकर जायेगी।
- अन्य देश के कारण उत्पन्न समस्या पर एक-दूसरे से विचार करेंगे।

मधेशी समस्या

मधेशी का अभिप्राय

- नेपाल में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र को ही मधेशी क्षेत्र कहा गया, जो नेपाल के पहाड़ी और मैदानी भाग के बीच का भाग है। इस मधेशी क्षेत्र में नेपाल के 22 जिले सम्मिलित है, जिनके जनपद की सीमा भारत की सीमा के साथ मिलती है।
- मधेशियों में भारतीय मूल के मधेशी हैं और नेपाली मधेशी भी है। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 40% से ज्यादा हिस्सा इस भाग में निवास करता है। नेपाल के कृषि उत्पादन का 65% तथा नेपाल के कुल राजस्व का 70% भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- मधेशी, मैथिली, भोजपुरी एवं हिन्दी भाषा बोलते हैं। इसलिए इनके सांस्कृतिक और वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं।

मधेशियों के साथ नेपाल में भेदभाव

- मधेशियों के साथ अनेक प्रकार के भेदभाव हुए। उदाहरण के लिए, वर्ष-1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशियों को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ा।
- मधेशियों के अनुसार, मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक कम हुआ है।
- मधेशी ये भी मानते हैं, कि भारत का दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केन्द्रित होता है और भारत भी मधेशियों के हितों की उपेक्षा करता है।

नेपाल सरकार का मधेशियों के बारे में दृष्टिकोण

- नेपाल सरकार मधेशियों को भारत समर्थक मानती है।
- माओवादियों और मधेशियों के बीच भी हिंसक संघर्ष हो चुके हैं।
- माओवादियों ने आरोप लगाया कि मधेशियों को भारत उकसाता है।

नेपाल और चीन की नजदीकी से भारत का नुकसान

- नेपाल अपना 60% आयात भारत के जरिये पूरा करता है। चीन के साथ समझौते से भारतीय बंदरगाहों पर नेपाल की निर्भरता खत्म हो जाएगी।
- हिमालय जो कि नेपाल और चीन के संपर्क में एक बाधक बना था, अब दोनों देशों को जोड़ने वाला बन गया है।
- ट्रांजिट एंड ट्रेड समझौता दक्षिण एशिया में नए समीकरण का सूत्रपात करेगा। चीन का नेपाल में प्रवेश भारत को घेरने की उसकी योजना का हिस्सा है।
- चीन द्वारा नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना भारतीय सीमाओं तक चीनी सैनिकों की पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- नेपाल-चीन के बीच रेल संपर्क की बहाली सिलिगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा बढ़ाएगी। यही एक मात्र कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है।
- नेपाल में चीन की मौजूदगी का अर्थ है कि भारत के अलगाववादियों और माओवादियों तक उसकी पहुंच बढ़ जाएगी।
- साथ ही भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा संबंधी दूसरी समस्याएं पैदा होंगी।

संभावित प्रश्न

नेपाल में कम्युनिस्ट के प्रस्तावित एकीकरण में खुलापन और विश्वसनीयता का अभाव है। नेपाल में व्याप्त इस राजनीतिक उथल-पुथल का भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हुए भारत के लिए नेपाल की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए।

The proposal of integration of communists in Nepal lacks openness and credibility. Discussing the impact of this political upheavel in Nepal on India, evaluate the significance of Nepal for India. (200 words)